

प्रेषक:

सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित:

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग:

देहरादून:

दिनांक: नवम्बर 17, 2009

महोदय,

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 में संशोधन करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास, उद्यानीकरण, वृक्षारोपण तथा भूमि विकास के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के राजपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है (इसका अंग्रेजी रूप ही पढ़ा जाये)।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता से अटल आदर्श ग्राम के रूप में अभिज्ञानित ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा धारित भूमि पर उक्त संदर्भित कार्य कराये जाएं।

परियोजना में चयनित ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण एवं नियोजन का कार्य कृषि विभाग के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। परियोजनाओं का आगणन कार्य विशेष के अनुसार संबंधित विभाग की अनुमोदित दरों के अनुरूप होगा। सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये ग्रामवार परियोजना सक्षम अधिकारी से तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे, जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना का कियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु धनराशि परियोजना स्वीकृति के पश्चात संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। इन कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के विकासखण्ड स्तरीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा भी उक्त परियोजनाओं का random आधार पर स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करया जायेगा।

कृपया समस्त अटल आदर्श ग्रामों में सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजना स्वीकृति का कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाये तथा इस योजना से मार्च 2011 तक अटल आदर्श ग्रामों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाये। वर्ष 2010-11 में चयनित परियोजनाओं को संतृप्त करने हेतु यथावश्यक लेबर बजट में प्राविधानित कर लिया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
Anshu Prakash
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या: /8-2/रा०ग्रा०रो०गा०यो०/2009-10 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मण्डलायुक्त कुमायुं/गढ़वाल मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. ✓ एन०आई०सी०, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

(ओम प्रकाश)
सचिव

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158]

No. 1158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SHRAVANA 2, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

का.आ. 1824(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का उपबंध।”

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरडीजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 में संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए :

1. का. आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का. आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का. आ. 2999(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2008

2725 GI/2009

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2009

S.O. 1824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

“(iv) provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008.”

[F.No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended vide following Notification Numbers :

1. S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008

MOST IMMEDIATE

No.11060/3/2009-NREGA
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi 110114
1st September 2009

The Principal Secretary/Secretary(Rural Development)
Government of

Subject:- Amendment to Schedule I Para 1(iv) of NREG Act

Ministry of Rural Development notified the amendment to Schedule I Para 1(iv) of NREG Act vide Notification dated 22nd July 2009 as under:-

"provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008."

2. In order to ensure due compliance with the amendment notified and creation of durable assets and strengthening the livelihood resource base of the rural poor, the following directions are issued in accordance with Section 27(1) of National Rural Employment Guarantee Act.

- i) Works on the land of Scheduled Castes and Scheduled Tribes households will be taken on priority. Once works on the lands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are saturated in a Gram Panchayat, works on lands of small and marginal farmers may be considered.
- ii) Works on lands of small and marginal farmers will be of water conservation and water harvesting like construction of dug wells and farm ponds, recharge structures on existing well and conveyance systems.

iii) Following conditions as notified vide Notification dated 18th June 2008 are also required to be fulfilled while executing the above said directions.

- a) The individual land owner shall be a Job Card holder and also work in the project;
- b) For each such project, the labour material ratio of 60:40 shall be maintained at the Gram Panchayat level;
- c) Projects shall be approved by the Gram Sabha and the Gram Panchayat and shall be part of the annual shelf of projects;
- d) No contractors or machinery shall be used in the execution of work;
- e) No machinery shall be purchased.



(Amita Sharma)
Joint Secretary to the Government of India
Tele: 2338 5027